

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी- अरविन्द कुमार जाखड़. (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक: 20.8.2014

प्रकरण संख्या: निगरानी/ 86/2014

देवसिंह पुत्र गुरमुखसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड न. 15 रावला तहसील घडसाना  
(निगरानीकर्ता)

बनाम

1. बाघ सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति मजबी निवासी 1 ए एम (5 बी.डी. के पास) तहसील घडसाना
2. सचिव ग्राम पंचायत 8 पी.एस.डी.(बी) रावला मण्डी तहसील घडसाना
3. सरपंच ग्राम पंचायत 8 पी.एस.डी.(बी) रावला मण्डी तहसील घडसाना  
(गैरनिगरानीकर्ता)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित:-

1. श्री योगेन्द्र बतरा अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री मनोहर लाल अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1
3. श्री राजेन्द्र सिंह अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 ता 3

:: निर्णय ::

दिनांक:-05.8.2022

1. निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता के पास वार्ड न. 15 रावला में पट्टा शुदा आवासीय भूखण्ड साईज उतर से दक्षिण 37 फुट व पूर्व से पश्चिम 81 फुट है। निगरानीकर्ता के इस आवासीय पट्टेशुदा भूखण्ड के पश्चिम में चिपता हुआ जैर निगरानी भूखण्ड साईज उतर से दक्षिण 105 फुट व पूर्व से पश्चिम 80 फुट वर्ष 1994 से आज तक निगरानीकर्ता के आधिपत्य व अधिकार में है। उक्त जैरनिगरानी भूखण्ड की तीन दिशा में चार दिवारी तथा चौथी में दिशा ए.एस. नहर की तरफ कच्ची चारदिवारी है जिसमें 10 फुट का गेट लगा हुआ है तथा पानी की टंकी का निर्माण किया हुआ है। निगरानीकर्ता के पट्टेशुदा भूखण्ड व जैर निगरानी भूखण्ड के मध्य कोई चार दिवारी नहीं है। दोनों भूखण्डों पर एकल निर्माण निगरानीकर्ता का है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 ने गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 व 03 से मिलीभगत कर जैर निगरानी भूखण्ड साईज 105 गुणा 80 में से पूर्व से पश्चिम 26 फुट व उतर से दक्षिण 60 फुट का पट्टा संख्या 38 दिनांक 31.3.2011 ग्राम पंचायत 8 पीएसडी (बी) से जारी करवा लिया। ग्राम पंचायत 8 पीएसडी (बी) द्वारा गृह विनियमितिकरण का निर्णय दिनांक 05.12.2011 को लिया जाकर इस विनियमितिकरण निर्णय के प्रकाश में संकल्प संख्या 1 दिनांक 06.02.2012 को लिया गया। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व व आक्षेपित संकल्प का निर्णय पारित करने से पूर्व न तो पंचायती राज अधिनियम के नियमों व आज्ञापक प्रावधानों की तथा ना ही निगरानीकर्ता को कोई सूचना दी तथा ना ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा मौका व कब्जा संबंधी जांच भी नहीं की गई। जैर निगरानी पट्टा संख्या 38 दिनांक 31.3.2011 में अंकित उक्त भूखण्ड पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 का कोई निर्माण या रिहायश नहीं है। ग्राम पंचायत ने आनन-फानन में पट्टा जारी किया है। अतः ग्राम पंचायत 8 पीएसडी (बी) के गृह विनियमितिकरण का निर्णय दिनांक 05.12.2011 और इस निर्णय के प्रकाश में लिया गया संकल्प संख्या 01 दिनांक 06.02.2012 व पट्टा संख्या 38 दिनांक 31.3.2011 निरस्त किया जावे।
2. निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर ग्राम पंचायत का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। गैरनिगरानीकर्तागण को जरिये नोटिस तलब किया गया। निगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री



अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

योगेन्द्र बतरा हाजिर आये। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहर लाल तथा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

3. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस सुनी गई। वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 16.7.2014 को गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 गैरनिगरानी भूखण्ड पर कब्जा करने की नीयत से आये तथा निगरानीकर्ता को उक्त भूखण्ड खाली करने की धमकी देने लगे तथा भूखण्ड का पट्टा अपने नाम से जारी होना बताया। तब निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 16.7.2014 को विकास अधिकारी, पंचायत समिति घडसाना के समक्ष नकल हेतु आवेदन किया गया जिस पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 01.8.2014 को सचिव ग्राम पंचायत 8 पीएसडी द्वारा निगरानीकर्ता को नकल दी गई। जानकारी की दिनांक से बिना किसी देरी के निगरानी अन्दर मियाद पेश की गई है। निगरानीकर्ता द्वारा जान बूझ कर हस्तगत किसी निगरानी देरी से पेश नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर निगरानी पेश करने की अनुमति प्रदान करे।
4. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस करते हुए लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से यह भलीभांती प्रकट है कि मुझ गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 को आवंटन से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा इस स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। तीन सदस्य पंच कमेटी ने इस विवादित स्थली की तथ्यात्मक रिपोर्ट ली, पडोसियों के बयान भी लिये गये तथा आवंटन से पूर्व आपत्तियां दर्ज करवाने हेतु जारी किये गये नोटिस के समय निगरानीकर्ता को उक्त आवंटन की जानकारी नहीं होती ऐसा संभव ही नहीं है। निगरानीकर्ता स्वच्छ हाथों से इस न्यायालय में नहीं आये है। क्योंकि निगरानीकर्ता यह निगरानी पेश ना करता तो उसे स्थायी समिति के समक्ष 30 दिवस में अपील पेश करनी पडती। अतः निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत के उक्त आदेश की भलीभांती जानकारी होते हुए भी देरी से यह निगरानी पेश की है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद स्वीकार योग्य नहीं है।
5. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में निगरानीकर्ता ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है। निगरानीकर्ता द्वारा धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का कोई प्रतिशपथ पत्र भी अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 ता 3 द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
6. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील निगरानीकर्ता ने दौराने बहस निगरानी मीमों के तथ्यों को दौहराया तथा कथन किया कि निगरानीकर्ता के पास वार्ड न. 15 रावला में पट्टा शुदा आवासीय भूखण्ड साईज उतर से दक्षिण 37 फुट व पूर्व से पश्चिम 81 फुट है। निगरानीकर्ता के इस आवासीय पट्टेशुदा भूखण्ड के पश्चिम में चिपता हुआ गैर निगरानी भूखण्ड साईज उतर से दक्षिण 105 फुट व पूर्व से पश्चिम 80 फुट वर्ष 1994 से आज तक निगरानीकर्ता के आधिपत्य व अधिकार में है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3 से मिली भगती कर उक्त भूखण्ड में से पूर्व से पश्चिम 26 फुट व उतर से दक्षिण 60 फुट का पट्टा संख्या 38 दिनांक 31.3.2011 जारी करवा लिया। जबकि ग्राम पंचायत 8 पीएसडी (बी) द्वारा गृह विनियमितकरण का निर्णय दिनांक 05.12.2011 को लिया जाकर इस विनियमितकरण निर्णय के प्रकाश में संकल्प संख्या 01 दिनांक 06.02.2012 को लिया है। जबकि विधिक रूप से उक्त समस्त कार्यवाही पट्टा जारी करने से पूर्व की जानी चाहिए थी। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व व आक्षेपित संकल्प का निर्णय पारित करने से पूर्व न तो पंचायती राज अधिनियम के नियमों व आज्ञापक प्रावधानों की पालना की गई तथा ना ही निगरानीकर्ता को कोई सूचना दी एवं ना ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से मौका व कब्जा संबंधी जांच भी नहीं की गई। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 में 50 वर्ष से



अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सुरतगढ़ (श्री गंगानगर)

अधिक पूर्व से निर्मित मकानों के विनियमितकरण हेतु 100/- रुपये शुल्क जमा करवाकर उनका विनियमितकरण करवाया जा सकता है। जबकि हस्तगत प्रकरण में जैरकार भूखण्ड पर वर्षों से निगरानीकर्ता के ही कब्जा में चला आ रहा है तथा निगरानीकर्ता द्वारा अपने कब्जा शुदा प्लाट साईज निगरानीकर्ता के ही कब्जा में चला आ रहा है तथा निगरानीकर्ता द्वारा अपने कब्जा शुदा प्लाट साईज 105 गुणा 80 वर्गफुट के एकल प्लाट पर कच्ची चार दीवारी जिसमें बड़ा गेट तथा पानी की टंकी शौचालय, व ट्रेक्टर ट्राली खड़ी करने जलाऊ लकड़ी रखने आदि कार्य हेतु स्थान बना रखा है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत विनियमितकरण हेतु उक्त ग्राम पंचायत का निवासी आवश्यक है। जबकि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 बाघ सिंह 5 बी.डी. तहसील घडसाना का निवासी है क्योंकि हस्तगत प्रकरण में गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 को भेजे गये नोटिस 5 बीडी के पते पर तामील हुए हैं जिससे यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 ग्राम पंचायत 8 पीएसडी (बी), रावला मण्डी का निवासी नहीं है। निगरानीधीन पट्टे पर लगाई गई दिनांक भी अलग अलग है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्राम पंचायत ने आनन फानन में पट्टा जारी किया है। उक्त पट्टे पर पट्टा जारी करने की दिनांक 31.03.2011 अंकित की गई है तथा संकल्प लेने की दिनांक 06.02.2012 अंकित की गई जिससे यह सिद्ध होता है कि पट्टा पहले जारी किया गया उक्त पट्टा बाबत संकल्प बाद में लिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये विधि विरुद्ध तारीके से पट्टा जारी किया गया है। अतः ग्राम पंचायत 8 पीएसडी (बी) के गृह विनियमितकरण का निर्णय दिनांक 05.12.2011 और इस निर्णय के प्रकाश में लिया गया संकल्प संख्या 01 दिनांक 06.02.2012 व पट्टा संख्या 38 निरस्त किया जावे। न्यायिक दृष्टांत 2016 (4) डीएनजे (राज) पेज 1799, 2015(2)डीएनजे (राज.) पेज 596, 2013 (3) आरएलडब्ल्यू पेज 2753 तथा राजस्थान पंचायती राज नियम 1995 के नियम 157 की ओर ध्यान दिलाया।

7. अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ने अपनी बहस में लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 166 में अपील का विशेष प्रावधान है तथा यह प्रावधान भी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत है तथा इस विशेष प्रावधान के होते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 (3) के निगरानी के सामान्य प्रावधानों को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 को जैर निगरानी भूखण्ड राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के तहत आवंटित किया गया है जिससे व्यथित होकर निगरानीकर्ता को पंचायत समिति की स्टैंडिंग कमेटी में अपील की जानी चाहिए थी। निगरानीकर्ता ने स्वयं के कब्जा में यह विवादित प्लाट होना दर्शाकर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 को आवंटित हुए इस विवादित प्लाट को अपनी इस निगरानी के जरिये चुनौती दी है। यदि वास्तव में आवंटन के समय यह प्लाट निगरानीकर्ता के कब्जा में होता तो आवंटन के समय मौका निरीक्षण एवं पंच कमेटी द्वारा तैयार की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट में तथा आस पास के पडोसियों द्वारा भी इस बाबत रिपोर्ट की गई होती। आवंटन के समय आपत्तियां दर्ज करवाने हेतु नोटिस भी जारी किये गये थे तब भी निगरानीकर्ता द्वारा अपने कब्जा के संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किये गये। मुझ गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 का पिछले 20 वर्षों से इस आवासीय भूखण्ड पर कब्जा है तथा भूखण्ड पर मकान व चार दिवारी बनाई हुई है। जो ग्राम पंचायत किये गये मौका जांच की रिपोर्ट व पंचों की रिपोर्ट से साबित है। मुझ गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 द्वारा ग्राम पंचायत को पूर्ण फीस अदा की है तथा ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया के तहत ही पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त की जावे तथा ग्राम पंचायत का आदेश यथावत रखा जावे। न्यायिक दृष्टांत Western Law Cases (raj) 1995 (1) पेज 243-244, Western Law Cases (raj) UC 2012 पेज 70-72 की ओर ध्यान दिलाया।

8. अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 ता 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी आदेश पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए तथा समस्त तथ्यों की जांच करके ही पारित किये गये हैं। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त की जाकर ग्राम पंचायत का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर गहनता से चिंतन, मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 अनुसार "जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हों और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो राशि जमा करवाकर पट्टा जारी किया जा सकेगा" उक्त नियम में 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों के लिए 100/- राशि



अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

निर्धारित की गई है। जबकि ग्राम पंचायत की पत्रावली में उपलब्ध पडोसियों के बयान, जंगीर सिंह पट्टा बनवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा शपथ पत्र ग्राम पंचायत के फर्द अहकाम में 20 वर्षों से गैरनिगरानीकर्ता का कब्जा माना है। राजस्थान पंचायत राज नियम 1998 के नियम 157 तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 (1) के तहत जारी किये गये आवारायीय भूमि के पट्टे की शर्त संख्या 01 अनुसार उक्त पट्टा पुराने घर पर कब्जा होने की स्थिति में या संनिर्मित किये जाने की स्थिति में जारी किया जा सकता है जबकि ग्राम पंचायत की पत्रावली में भी गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 का मकान होने संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र में भी प्लॉट पर ही कब्जा होना अंकित किया है ना कि किसी मकान पर। हस्तगत पत्रावली में भी गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 का विवादित प्लॉट पर मकान बना होने संबंधी कोई साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। ग्राम पंचायत जैर निगरानी पट्टा जिन दस्तावेजों यथा पडोसियों के बयान, मौका नक्शा, कमेटी की जांच रिपोर्ट आदि पर जारी किया है, उन पर दिनांक अंकित नहीं है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 ने पट्टा बनाने हेतु दिनांक 05.10.2011 को आवेदन किया गया जबकि ग्राम पंचायत द्वारा संख्या 01 दिनांक 31.03.2011 को ही पट्टा संख्या 38 जारी कर दिया और उक्त पट्टा पर संकल्प संख्या 01 दिनांक 06.02.2012 की अनुपालना में दिनांक 06.02.2012 को जारी किया जाना अंकित किया है। चूंकि जब प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र ही दिनांक 05.10.2011 को किया गया है तो पट्टा दिनांक 31.03.2011 को जारी किया जाना सन्देहास्पद है। उक्त पट्टा संकल्प संख्या 01 दिनांक 06.02.12 की अनुपालना में दिनांक 31.3.2011 को जारी किया है जिससे यह साबित होता है कि उक्त पट्टा संकल्प जारी करने से पहले जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत विनियमितकरण हेतु प्रार्थी का उक्त ग्राम पंचायत का निवासी होना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 को भेजे गये नोटिस 1 ए एम (5 बीडी के पास) के पते पर तामील हुए है जिससे यह स्पष्ट है कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 ग्राम पंचायत 8 पीएसडी (बी), रावला मण्डी का निवासी नहीं है। वकील निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में भली भांती चस्प होते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का उलंघन कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो विधिविरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत 8 पीएसडी 'बी' का पट्टा संख्या 38 दिनांक 31.3.2011 निरस्त किया जाता है। निर्णय प्रति सहित ग्राम पंचायत का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अरविन्द कुमार जाखड़)  
 जिला कलेक्टर  
 सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)